दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: **19.01.2023.**

निर्णय की तिथि: **03.02.2023**

सि.वि.(मु.) 655/2022, सि.वि.आ. 30320/2022 (स्थगित), सि.वि.आ. 42224/2022 (निपटान) और सि.वि.आ. 42606/2022 (तिथि में परिवर्तन)

आकृति कपूर ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मालविका राजकोटिया के साथ सुश्री आकृति त्यागी स्वयं याचिकाकर्ता भी, अधिवक्तागण

बनाम

अभिनव अग्रवाल ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री गीता लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री मानस अग्रवाल, सुश्री कामाक्षी गुप्ता, अधिवक्तागण और सुश्री काव्या अग्रवाल, अधिवक्तागण

कोरमः
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा पल्ली

<u>न्या. रेखा पल्ली</u>

<u>निर्णय</u>

1. वर्तमान याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, साढ़े पांच वर्ष की बच्ची की माँ द्वारा दायर किया गया है, जो वि. सं. 29/2020 में विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.2022 को पारित आदेश को

चुनौती देने की माँग करती है। आक्षेपित आदेश के द्वारा, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने मुलाकात के अधिकारों में संशोधन की माँग करने वाले दोनों पक्षकारों द्वारा दायर आवेदनों के निपटान को स्थगित करते हुए, पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ मामले को स्थगित कर दिया है।

2. अभिलेख पर से जो संक्षिप्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स सामने आया है, वह यह है कि पक्षकारों ने हिंदू धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार 04.02.2013 को विवाह किया था। उनकी शादी के तुरंत बाद, उनके बीच विवाद पैदा हो गए; परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता, गर्भावस्था की स्थिति में, अपने माता-पिता के घर वापस चली गई जहाँ उसने 09.03.2017 को एक लड़की अनीशा को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद, हालाँकि याचिकाकर्ता, प्रत्यर्थी के अनुरोध पर, अपने ससुराल लौट आई, परन्तु पक्षकार अपने विवादों को हल नहीं कर सके और वह 01.10.2017 को, पुनः अपने माता-पिता के घर चली गई। तब से याचिकाकर्ता और नाबालिग बच्चा याचिकाकर्ता के माता-पिता के घर पर ही रह रहे हैं।

3. चूँकि पक्षकार अपने मतभेदों को दूर करने में समर्थ नहीं थे, इसलिए उन्होंने 12.11.2018 को एक समझौता किया, जिसके अनुसार, वे न केवल आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए सहमत हुए, बल्कि इस बात पर भी सहमत हुए कि नाबालिग बच्चे की स्थायी संरक्षण याचिकाकर्ता के पास रहेगी। इस समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी हर महीने के पहले रविवार को पांच

घंटे के लिए नाबालिग बच्चे से मिलने का हकदार था, यह व्यवस्था छह महीने तक जारी रहनी थी। 27.11.2018 को, पक्षकारों ने दिनांक 12.11.2018 को समझौता करार में उल्लिखित शर्तों पर अपनी-अपनी पहली समावेदन याचिकाएं दायर कीं, जिस समावेदन को विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। हालाँकि, दूसरा समावेदन दायर करने से पहले, 25.05.2019 को पक्षकारों ने एक और समझौता किया, जिससे पक्षकारों के बीच पहले सहमत मुलाकात के अधिकारों को संशोधित किया गया। इस संशोधित समझौते की शर्तों के अनुसार, प्रत्यर्थी को हर महीने के पहले रविवार को पांच घंटे के मौजूदा मुलाकात के अधिकारों के अलावा, रात भर मुलाकात करने का अधिकार दिया गया था। तदनुसार प्रत्यर्थी को महीने के हर चौथे शनिवार को शाम को याचिकाकर्ता के घर से बच्चे को लेने और रविवार शाम को उसे वापस छोड़ने का अधिकार था। उन्हें आगे गर्मी की छुट्टियों में पांच दिनों के लिए और सर्दियों की छुट्टियों में तीन दिनों के लिए बच्चे की विशेष संरक्षण दी गई थी, इसके अलावा दिवाली के त्योहार के साथ-साथ बच्चे के जन्मदिन पर भी तीन घंटे की विशेष संरक्षण दी गई थी। इस समझौते के अनुसार, पक्षकारों के बीच यह सहमति बनी कि याचिकाकर्ता अदालत की अनुमति के बिना बच्चे को देश से बाहर ले जाने का हकदार नहीं होगा।

4. इस संशोधित समझौते की शर्तों के आधार पर, पक्षकारों ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ख(2) के तहत अपनी दूसरी समावेदन याचिका दायर

की, जिसे विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा 20.07.2019 को अनुमति दी गई, जिससे उनकी शादी समाप्त हो गई। इसके बाद प्रत्यर्थी ने जनवरी, 2020 में पुनर्विवाह कर लिया, जो तथ्य याचिकाकर्ता का दावा है, उसके संज्ञान में लंबे समय तक नहीं लाया गया था, यद्यपि समझौता करार के अनुसार बच्चा नियमित रूप से उससे मिलने जाता था। मार्च, 2020 में, जब कोविड-19 की महामारी शुरू हुई, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दिए जाने तक बच्चे से शारीरिक मुलाकात को स्थगित करने का अनुरोध किया और उससे वीडियो कॉल पर बच्चे के साथ बातचीत कराने का अनुरोध किया, जो सुझाव उसे स्वीकार्य नहीं था। हालांकि, महामारी की स्थिति में सुधार होने के बाद, समझौता करार के अनुसार बच्चे से शारीरिक मुलाकात फिर से शुरू हो गई।

5. इनमें से एक मुलाकात के दौरान, जब प्रत्यर्थी ने 05.07.2020 को याचिकाकर्ता के घर से बच्चे को ले गया, तो उसने इस आधार पर उसका कोविड-19 परीक्षण कराया कि उसमें कोविड के लक्षण विकसित हो गए हैं। हालाँकि, बच्चा निगेटिव पाया गया। बच्चे का अनावश्यक रूप से परीक्षण किए जाने से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने 27.08.2020 को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें सहमत मुलाकात अधिकारों में संशोधन की माँग की गई और प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थी को केवल वीडियो कॉल द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ बातचीत करने

का निर्देश दिया जाए। हालाँकि, जैसे-जैसे शहर में कोविड के मामलों की संख्या बढ़ी, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी को बच्चे से शारीरिक रूप से मिलने की अनुमति नहीं दी।

6. नतीजतन, अक्टूबर, 2020 में, प्रत्यर्थी ने अपने मिलने के अधिकारों को लागू करने के लिए निष्पादन याचिका संख्या 20/2020 दायर की। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने यह देखने के बाद कि कोविड-19 महामारी के कारण शारीरिक मुलाकात अनुकूल नहीं होंगी, अपने दिनांक 05.12.2020 के आदेश द्वारा, प्रत्यर्थी को केवल वीडियो कॉल द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। इस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा सि.वि.(मु.) 641/2020 के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें इस न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति से मुलाकात के अधिकारों को संशोधित किया और प्रत्यर्थी को हर पहले और चौथे शनिवार को सुबह 11 बजे याचिकाकर्ता के घर से नाबालिग बच्चे को ले जाने का निर्देश दिया, बशर्ते कि प्रत्यर्थी के परिवार के सदस्य, जिसके नाबालिग बच्चे के संपर्क में आने की संभावना थी, उसकी ऐसी हर मुलाकात से पहले कोविड-19 की जांच की जाएगी। इसके बाद कुछ समय के लिए नियमित रूप से शारीरिक मुलाकात होती रही, लेकिन बाद में कोविड के मामलों की संख्या में वृद्धि और प्रत्यर्थी के कोविड से संक्रमित होने के कारण, याचिकाकर्ता ने फिर से प्रत्यर्थी से वीडियो कॉल पर नाबालिग बच्चे से बात करने का अनुरोध किया।

7. अप्रैल 2021 में, याचिकाकर्ता ने भी पुनर्विवाह किया और उसके पति डॉ. रितेश कनोत्रा फीनिक्स, एरिज़ोना, अमेरिका के निवासी हैं। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी के साथ अमेरिका में रहने की इच्छा रखते हुए, 09.06.2021 को विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें मुलाकात के अधिकारों की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन की माँग की गई। प्रत्यर्थी ने इस आधार पर आवेदन का विरोध किया कि याचिकाकर्ता का अमेरिका में रहने का इरादा प्रत्यर्थी को समझौता करार द्वारा उसे दिए गए मुलाकात के अधिकारों और रात भर रहने देने से वंचित करने का प्रयास था। प्रत्यर्थी द्वारा यह कहा गया था कि नाबालिग बच्चे और उसके बीच संबंध के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसे मिलने का अधिकार दिया गया था और यह कि मिलने के अधिकारों में कटौती का बच्चे के साथ उसके संबंध पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही, प्रत्यर्थी ने इस आधार पर बच्चे की संरक्षण की माँग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया कि याचिकाकर्ता के साथ उसका अमेरिका में रहना उसके हित में नहीं होगा और उसे अपने ही देश में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने पहले, प्रत्यर्थी को सूचित किए बिना, बच्चे को अपने माता-पिता के संरक्षण में छोड़कर अमेरिका की यात्रा की थी, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि वह अपने बच्चे के कल्याण के बारे में चिंतित नहीं थी और इसलिए, उसने तर्क दिया कि उसे बच्चे का संरक्षण दिया जाना चाहिए।

8. विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने पक्षकारों की विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, पक्षकारों को अपने-अपने संबंधित साक्ष्य को पेश करने का निर्देश देते हुए दिनांक 27.05.2022 को आक्षेपित आदेश पारित किया। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने राय दी कि चूँकि मामले में पक्षकारों की नाबालिग बेटी की संरक्षण में संशोधन/मंजूरी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, जिन्होंने एक-दूसरे के खिलाफ आरोप लगाए थे, इसलिए विवादित तथ्यों का निर्धारण साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के द्वारा इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

9. 17.08.2022 को, जब वर्तमान याचिका को प्रारंभिक विचार के लिए लिया गया था, तो इस न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी.पी.सी.) के आदेश X नियम 2 के तहत पक्षकारों की मौखिक रूप से जांच करना उचित समझा और इसलिए पक्षकारों को 30.08.2022 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आगे कहा कि वह आदेश X सी.पी.सी. के तहत मामले के तथ्यों से परिचित अन्य व्यक्तियों को अपना बयान दर्ज करने के लिए बुला सकता है। इस आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर की, जिसका निपटान 10.10.2022 को यह अभिनिर्धारित करते हुए किया गया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक न्यायसंगत और निष्पक्ष निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए

पारित किया गया था। हालाँकि, शीर्ष न्यायालय ने दोनों पक्षकारों के लिए एक उचित स्तर पर इस न्यायालय के समक्ष प्रतिपरीक्षा के अपने अधिकार सहित अपने सभी आपत्तियों को उठाने के लिए खुला छोड़ दिया है, जिन आपत्तियों पर उनके गुणागुण के आधार पर विचार किया जाना आवश्यक था।

10. नतीजतन, दिनांक 17.08.2022 आदेश के अनुसार, 02.11.2022 को आदेश X नियम 2 सी.पी.सी. के तहत पक्षकारों की जांच की गई। याचिकाकर्ता के माता-पिता, उसके ससुर और प्रत्यर्थी की माँ के बयान भी उसी तारीख को दर्ज किए गए थे। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा याचिकाकर्ता के पति डॉ. कनोत्रा से भी पूछताछ की। यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ. कनोत्रा ने इस न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा कि नाबालिग बच्चे को हमेशा वह अपने बच्चे की तरह मानेगा।

11. तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर ध्यान देने के बाद, मैं अब पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़ सकता हूँ।

12. याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालविका राजकोटिया ने यह तर्क देते हुए शुरुआत की कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा है कि मामले में तथ्य के कोई विवादित प्रश्न शामिल नहीं थे, पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रतिपरीक्षा का सामना करने का निर्देश दिया गया। उनका तर्क है कि दोनों पक्षकार स्वीकृत तथ्यों के आधार पर पारस्परिक रूप से सहमत मुलाकात करने के

समझौते में संशोधन की माँग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के अमेरिका में स्थित डॉक्टर से शादी करने के तथ्य के बारे में न तो कोई विवाद है और न ही इस तथ्य के बारे में कि नाबालिग बच्चा जन्म से ही याचिकाकर्ता की संरक्षण में है। इसके अलावा, यह भी एक स्वीकृत स्थिति है कि दोनों पक्षकारों ने 2018 और 2019 में पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की थी कि बच्चे का संरक्षण याचिकाकर्ता/माँ के पास रहेगी। इसलिए, वह प्रस्तुत की कि विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देकर आवेदनों के निपटान को स्थगित करने में गंभीर गलती की है।

13. इसके बाद वह प्रस्तुत की कि अन्यथा भी, पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देने वाला आक्षेपित आदेश, उन आवेदनों के न्यायनिर्णयन में अनावश्यक रूप से देरी करेगा, जिसे नाबालिग बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए, जल्द से जल्द निपटाया जाना आवश्यक है। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत है जिसमें परिकल्पना की गई है कि जब भी संभव हो संक्षिप्त प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के बयान की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए, वह प्रस्तुत की कि अधिनियम विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को प्रक्रिया और साक्ष्य के कठोर नियमों के पालन से छूट देता है और इसकी धारा 10(3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय किसी समझौते पर

पहुंचने के लिए या एक पक्षकार द्वारा कथित और दूसरे द्वारा अस्वीकृत किए गए तथ्यों की सच्चाई पर पहुंचने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। ***निशा हनीफा बनाम अब्दुल लतीफ और अन्य, (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन केर. 1556***, में केरल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करके वह प्रस्तुत की कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को अपनी प्रक्रिया की तरीका चुनने के लिए दी गई शक्ति इस तथ्य का संकेत है कि यह प्रक्रियात्मक कानूनों की सख्ती और कठोरता द्वारा बाध्य नहीं है। इसके अलावा, विद्वान परिवार न्यायालयों को सामान्य सिविल न्यायालयों की तरह काम करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें अपनी प्रक्रिया अपनाकर मामले की सच्चाई की जांच करने के लिए पूछताछ करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान मामले में, एक बार जब प्रत्यर्थी ने समझौता करते समय, वर्ष 2018 और 2019 दोनों में, स्वेच्छा से सहमति व्यक्त की थी कि बेटी की संरक्षण याचिकाकर्ता के पास होगी, जो बच्चे की एकमात्र देखभाल करने वाली होगी, अब प्रत्यर्थी द्वारा लगाए जाने वाले आरोप याचिकाकर्ता द्वारा अमेरिका में रहने की माँग करने वाले आवेदन का केवल एक प्रतिरोध था। वह प्रस्तुत की कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि प्रत्यर्थी द्वारा लगाए गए प्रेरित आरोप नजरअंदाज किए जाने योग्य थे क्योंकि वे उसके द्वारा केवल उसके विवाहित जीवन में बाधा पैदा करने के लिए लगाए गए थे।

14. इसके बाद वह प्रस्तुत की कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय, साक्ष्य अभिलेखन का निर्देश देते हुए, जिसे पूरा होने में वर्षों लगेंगे, यह समझने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता के आवेदन के न्यायनिर्णयन में कोई भी देरी वस्तुतः उसे अपनी नाबालिग बेटी और एक खुशहाल विवाहित जीवन के बीच चयन करने के बराबर होगी। उसका कहना है कि इससे न केवल याचिकाकर्ता को बल्कि उसकी नाबालिग बच्ची को भी अपूरणीय कठिनाई होगी जो अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करने के लिए उत्सुक है। इन आवेदनों के लंबित रहने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता जिसकी शादी अप्रैल, 2021 में हुई थी, वह अभी भी अमेरिका में अपने पति के पास नहीं जा पायी है और इसलिए, अपनी शादी के लगभग दो साल बाद भी अपने पति के बिना रहने के लिए मजबूर है। इसलिए, वह प्रार्थना करती है कि पहले से ही हुई देरी के कारण, यह न्यायालय, अमेरिका में रहने की माँग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन पर तेजी से निर्णय ले सकता है।

15. अपनी अभिवचन के समर्थन में कि याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्चे के साथ अमेरिका में रहने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, सुश्री राजकोटिया प्रस्तुत की कि वह जन्म लेने के बाद से ही नाबालिग बच्चे की एकमात्र देखभाल करने वाली और संरक्षक रही हैं और यह अपने आप में बेटी को यह तसल्ली देता है कि उसकी माँ उससे प्यार करती है, जिस स्थिति को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इस स्थिति में कोई भी परिवर्तन बच्चे के सर्वोत्तम

हित में नहीं होगा, खासकर जब यह स्पष्ट हो कि प्रत्यर्थी केवल याचिकाकर्ता के विवाहित जीवन को नष्ट करने के लिए एक उपकरण के रूप में बच्चे का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। याचिकाकर्ता पेशे से एक डॉक्टर है जो अपने पति के पास जाने और जल्द से जल्द अपनी डॉक्टरी फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका में रहना चाहती है और उसे ऐसी स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए जहां उसे अपने बच्चे और अपने विवाहित जीवन और करियर के बीच चयन करना हो। दूसरी ओर, यदि याचिकाकर्ता को बच्चे के साथ अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाती है, तो वह न केवल अपने करियर में प्रगति कर पाएगी, बल्कि यह नाबालिग बेटी के हित में भी होगा क्योंकि बच्चा, वह तर्क दी कि, न केवल अमेरिका में एक खुशहाल परिवार में बड़ा होगा, बल्कि उसके समग्र विकास के लिए बेहतर रास्ते भी होंगे।

16. ***विक्रम वीर वोहरा बनाम शालिनी भल्ला (2010) 4 एस.सी.सी. 209, रितिका शरण बनाम सुजॉय घोष, सिविल अपील सं. 3544-45/2020 और रोहित तम्मना गौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य ए.आई.आर. 2002 एस.सी.SC 3511,*** में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करते हुए वह प्रस्तुत की कि यह केवल बच्चे का कल्याण ही है जिस पर न्यायालय द्वारा संरक्षण मामलों का निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए। वह तर्क दी की विद्वान कुटुम्ब न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोप मुलाकात के अधिकारों को तय करने के

लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जिसे बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए वह ***अनुराधा शर्मा बनाम अनुज शर्मा (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन बम. 1489*** में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा की है। इस प्रकार उसका अभिवचन, यह है कि उन मामलों में जहां संरक्षण के हस्तांतरण की माँग की जाती है, सामान्य परीक्षण बच्चे के सर्वोत्तम हितों का पता लगाने के लिए होता है और यह संभावना हमेशा माता-पिता के पक्ष में होती है जो बच्चे की निरंतर देखभाल करते हैं। वर्तमान मामले में, नाबालिग बच्ची, जो अपने जन्म के बाद से ही याचिकाकर्ता के साथ रह रही है, उसे बाल्य काल से ही उससे सारा प्यार और स्नेह मिल रहा है और यह याचिकाकर्ता ही है जो उसके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रही है। अपनी माँ से प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन पाकर बड़ी हुई नाबालिग बेटी का भी उससे गहरा लगाव है और इसलिए इस व्यवस्था को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

17. सुश्री राजकोटिया ने आगे प्रस्तुत की कि प्रत्यर्थी का अभिवचन कि याचिकाकर्ता अपनी नाबालिग बेटी की देखभाल करने के लिए अयोग्य है क्योंकि उसने उसके विकास के शुरुआती वर्षों के दौरान उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं किया और इसलिए, उसे विशेष संरक्षण दी जानी चाहिए, पूरी तरह से गलत है। नाबालिग बच्चा जन्म से ही याचिकाकर्ता के साथ रह रहा है और वह अकेली ही बाल्य काल से ही उसकी जरूरतों और स्वास्थ्य का ध्यान रख रही

है। प्रत्यर्थी ने नाबालिग बेटी को जन्म लेते ही छोड़ दिया और याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना कुछ समय के लिए सिंगापुर भी चला गया। यह तथ्य कि पक्षकारों के आपसी तलाक के समय, प्रत्यर्थी इस बात पर सहमत था कि नाबालिग बेटी की संरक्षण याचिकाकर्ता के पास रहेगी, भी इस तथ्य को इंगित करती है कि वह भी हमेशा इस बात से अवगत था कि याचिकाकर्ता बच्चे की संरक्षण करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। इसके अलावा, पारस्परिक रूप से सहमत सीमित मुलाकात के अधिकारों के बावजूद, प्रत्यर्थी ने मुलाकात के अधिकारों को बढ़ाने के लिए नहीं कहा; जब तक कि याचिकाकर्ता ने अपनी शादी के बाद अमेरिका में रहने की माँग नहीं की। वह तर्क दी कि प्रत्यर्थी, अब याचिकाकर्ता के खिलाफ अयोग्य माँ होने के निराधार आरोप लगाकर, उसे बच्चे की संरक्षण की माँग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो हमेशा से याचिकाकर्ता के साथ रही है।

18. वह आगे प्रस्तुत की कि प्रत्यर्थी का अभिवचन कि याचिकाकर्ता नाबालिग बच्चे को उसके जैविक पिता से अलग करना चाहता है, भी बिना किसी आधार के है। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता का बेटी को उसके पिता से अलग करने का कोई इरादा नहीं था, इस तथ्य से स्पष्ट है कि भले ही नाबालिग बच्चे के पास हमेशा से अमेरिका का वीजा था जब तक कि उसे प्रत्यर्थी द्वारा 30.04.2021 को रद्द नहीं कर दिया गया था, याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुमति लिए बिना देश नहीं छोड़ा था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी के मिलने के

अधिकारों में कोई कटौती की माँग नहीं कर रहा है, बल्कि केवल उसके समायोजन की माँग कर रहा है ताकि बच्चे का उसके साथ रहना जारी रह सके और एक प्रेमपूर्ण वातावरण में बड़ा हो सके। ***इशिता साहू बनाम राजस्थान राज्य, (2020) 3 एस.सी.सी. 67*** में शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने मुलाकात अधिकारों के अलावा संपर्क अधिकारों की अवधारणा पर प्रकाश डाला है, वह प्रस्तुत की कि जब भी याचिकाकर्ता छुट्टियों के दौरान जितनी अवधि के लिए भारत आएगी उतनी अवधि के लिए नाबालिग बच्चे की संरक्षण प्रदान करके प्रत्यर्थी के मुलाकात के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार है या किसी भी समय जब प्रत्यर्थी अमेरिका की यात्रा करने का विकल्प चुनता है।

19. *इसके विपरीत*, प्रत्यर्थी की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री गीता लूथरा यह तर्क देते हुए रिट याचिका की पोषणीयता का विरोध की कि आक्षेपित आदेश में कोई दुर्बलता या विकृति नहीं है ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी दी जा सके। विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने सभी तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संरक्षण प्रदान करने और मौजूदा संरक्षण आदेश में संशोधन के संबंध में तर्कपूर्ण और सकारण आदेश पारित किया है और पक्षकारों को अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वह प्रस्तुत की कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय का पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत

करने का यह निर्देश वास्तव में यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक था कि क्या संरक्षण के आदेशों में संशोधन के लिए कोई आदेश माँगा गया था।

20. ***पुरी इन्वेस्टमेंट्स बनाम यंग फ्रेंड्स एंड कंपनी (2022) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 283, गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गौयल (2022) 4 एस.सी.सी. 181*** और ***सेलिन कोएल्हो परेरा बनाम उल्हास महाबलेश्वर खोलकर (2010) 1 एस.सी.सी. 217***, में उच्चतम न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करके वह प्रस्तुत की कि यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपील न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती है और इसलिए, अपने विचारों को विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के साथ प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। यह तभी होता है जब किसी प्राधिकारी का निर्णय विकृत पाया जाता है और न्याय की हत्या हो सकती है कि न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है। वर्तमान मामले में, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय का निर्णय एक सुविचारित आदेश है, जिसे किसी भी तरह से विकृत नहीं कहा जा सकता है। साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश याचिकाकर्ता के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा और दूसरी ओर, न्यायालय को न्यायसंगत और उचित निर्णय लेने में सहायता करेगा कि क्या मुलाकात के अधिकारों को संशोधित किया जाना चाहिए और बच्चे का संरक्षण प्रत्यर्थी/पिता को दी जानी चाहिए।

21. इसके बाद वह प्रस्तुत की कि अन्यथा भी, पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के आलोक में, मुलाकात के अधिकारों के संशोधन का मुद्दा केवल पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य पर विचार करने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा उचित माना गया है। जब तक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक प्रत्यर्थी यह प्रदर्शित नहीं कर पाएगा कि याचिकाकर्ता ने न केवल अपने पति डॉ. कनोत्रा से मिलने के लिए अमेरिका की यात्रा की थी, अपने साढ़े पांच साल के बच्चे को अपने दादा-दादी के पास छोड़ दिया था, बल्कि वर्ष 2018 में टीकाकरण की नियत तिथि को याद रखने में भी पूरी तरह से लापरवाही बरती थी। इसके अलावा, जब बच्चे की बांह की हड्डी टूट गई थी, तब भी याचिकाकर्ता उसे नियमित रूप से फिजियोथेरेपी सत्रों ले जाने के बजाय अमेरिका चली गयी, उसी दिन उसका प्लास्टर हटाया गया था। वह प्रस्तुत की कि बच्चे के कल्याण के संबंध में ऐसे प्रश्न, केवल पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं, जिसके लिए वह ***सुमेधा नागपाल बनाम दिल्ली राज्य (2000) 9 एस.सी.सी. 745*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा की है। अपने अभिवचन के समर्थन में, वह ***एस. वेंकट राजा बनाम डॉ. ए.बी. चित्रा (2005) एस.सी.सी. ऑनलाइन मद्रा. 698*** में मद्रास उच्च न्यायालय के और ***प्रकाश बनाम अक्कमहादेवी (2000) एस.सी.सी.***

ऑनलाइन कर्णा. 497 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा की है।

22. इसके बाद वह प्रस्तुत की कि आदेश X नियम 2 सी.पी.सी. के तहत इस अदालत द्वारा दर्ज किए गए पक्षकारों के बयान शपथ के तहत नियमित जांच का विकल्प नहीं हो सकता है। ***कपिल कोरपैक्स (पी) लिमिटेड बनाम हरबंस लाल (2010) 8 एस.सी.सी. 452***, में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके वह यह तर्क दी कि आदेश X नियम 2 के तहत दर्ज किए गए पक्षकारों के बयान केवल विवाद का पता लगाने और उसे कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग विवादास्पद मुद्दों के न्यायनिर्णयन के लिए नहीं किया जा सकता है, जिसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सकता है। एक बार जब विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, तो न्यायालय ने उन्हें उचित रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है, जो उन्हें सच्चाई को स्पष्ट करने के लिए गवाहों से प्रतिपरीक्षा करने में भी सक्षम बनाएगा। ***मध्य प्रदेश राज्य बनाम चिंतामन सदाशिव वैशम्पायन ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1623, अयुबखान नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2013) 4 एस.सी.सी. 465 और आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले (1984) 2 एस.सी.सी. 183,*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करके वह तर्क दी कि प्रतिपरीक्षा प्रत्येक मुवक्किल के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण

अधिकार है, जिसे किसी भी तरह से कम नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि यह न्यायालय मुलाकात के अधिकारों के संशोधन के संबंध में पक्षकारों के आवेदनों के साथ-साथ रहने की माँग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन पर भी निर्णय लेता है, तो यह पक्षकारों को इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के उनके समान रूप से महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर देगा, यदि वे विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश से व्यथित हैं। वह प्रस्तुत की कि कानून का निर्माण होने के कारण अपील करने के अधिकार को केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता चाहता है कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के बजाय, इस न्यायालय को स्वयं उसके लंबित आवेदनों पर निर्णय लेना चाहिए, जिसे विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने पाया है, उचित रूप से निर्णय पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही लिया जा सकता है।

23. सुश्री लूथरा ने आगे कहा कि किसी भी स्थिति में, इस बाल्य काल में बच्चे को अमेरिका में रहने से उसके समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि बच्चे को याचिकाकर्ता के साथ अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाती है, तो यह पिता और बच्चे के बीच के संबंध को भी कमजोर करेगा क्योंकि प्रत्यर्थी मौजूदा नियमित बातचीत के मुकाबले वर्ष में केवल एक या दो बार बच्चे से मिल पाएगा, जैसा दोनों पक्षकारों के बीच पहले से ही सहमति हुई है। उनका कहना है कि यह पिता को बच्चे के साथ उसके जीवन के महत्वपूर्ण चरणों के

दौरान जुड़े रहने से वंचित कर देगा और उस घनिष्ठ संबंध को भी गंभीर रूप से खराब कर देगा जो बच्चा का वर्तमान में पिता के साथ है। ***रुचि माजू बनाम संजीव माजू (2011) 6 एस.सी.सी. 749*** में शीर्ष न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखते हुए, वह प्रस्तुत की कि नाबालिग बेटी के जीवन में पिता की देखभाल और मार्गदर्शन के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए, यह आवश्यक है कि माता-पिता के संपर्क में रहें और खुशी, दुख, सीखने आदि के सभी क्षणों को साझा करें। इसके अलावा, एक बार जब विधि आयोग की रिपोर्ट और बॉम्बे दिशानिर्देश भी बच्चे और माता-पिता के बीच नियमित रूप से शारीरिक मुलाकातों के महत्व पर जोर देते हैं, तो याचिकाकर्ता को अनुमति देना, जिसका आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह नाबालिग बच्चे की भलाई के प्रति चिंतित नहीं है, यदि दी जाती है, तो यह न केवल नाबालिग बच्चे के हित के लिए हानिकारक होगा, बल्कि पिता को नियमित रूप से और लगातार बच्चे से मिलने से भी वंचित कर देगा। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने अमेरिका में रहने का प्रस्ताव रखा है, नाबालिग बच्चे का संरक्षण उसे देने का यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता है क्योंकि आवश्यक कारक जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है, वह है पिता और बच्चे के बीच संबंध पर प्रस्तावित निर्णय का संभावित प्रभाव।

24. वह प्रस्तुत की कि इस प्रकार से रहने पर अमेरिका के न्यायालयों द्वारा भी अनुकूल रूप से विचार नहीं किया गया है, जिसके लिए वह ***ला मुस्गा***

पुनर्विवाह, 32 कैल. 4th 1072 और दघिर बनाम दघिर 441 एन.वाई.एस 2nd 494, में कैलिफोर्निया के उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भरोसा की है। वह ***पोलक बनाम पोलक, 181 एरिज. 275*** में एरिज़ोना के अपील न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा की है। यह तर्क देने के लिए कि ऐसे मामलों में जहां माँ के यात्रा करने/रहने के अधिकार की तुलना में पिता के संरक्षण के अधिकार का प्रश्न शामिल है, सबूत का भार हमेशा संरक्षक माता-पिता पर होता है ताकि यह दिखाया जा सके कि बच्चे का रहना उसके सर्वोत्तम हित में है और यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि बच्चे और माता-पिता के बीच सार्थक संबंध कायम रहे। एरिजोना के न्यायालयों ने एक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाया है कि बच्चे को अधिमानतः उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए जहां उसका जन्म हुआ था। वह तर्क दी कि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा इतनी कम उम्र में अपनी नाबालिग बेटी को छोड़कर अमेरिका की यात्रा करने का कृत्य, जब उसे उसके प्यार और स्नेह की आवश्यकता थी, जब वह डॉ. कनोत्रा के साथ रहने के लिए गई थी जब वह भारत आई थी, बच्चे को जरूरी टीकाकरण और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल से वंचित करना, ऐसी घटनाएं थीं जो स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं कि याचिकाकर्ता अपने नाबालिग बच्चे के कल्याण के प्रति चिंतित नहीं थी। इसलिए, वह प्रस्तुत करती है कि एक बार निर्विवाद तथ्यों से ही, यह स्पष्ट हो जाता है कि याचिकाकर्ता एक लापरवाह माँ रही है, जो अपने बच्चे की तुलना

में अपने विवाहित जीवन के बारे में अधिक चिंतित रही है, रहने के लिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और पिता, जो हर तरह से उसकी देखभाल करने के लिए योग्य है, के संरक्षण में नाबालिग बच्चे को रहने दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब वह यह करने के लिए तैयार हैं कि जब कभी याचिकाकर्ता भारत आयेगा, तो वह नाबालिग बच्चे का विशेष संरक्षण उसे देगा। इसलिए वह याचिका खारिज करने की प्रार्थना करती है।

25. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, मैंने पाया कि आक्षेपित आदेश के द्वारा, विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने राय दी है कि चूँकि मुलाकात के अधिकारों में संशोधन और फ़ेरबदल के लिए आवेदन में तथ्यों का विवादित प्रश्न शामिल है, इसलिए पक्षकारों को अपनी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए और प्रतिपरीक्षा का भी सामना करना चाहिए। पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, पहले आक्षेपित आदेश के प्रासंगिक उद्धरणों पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैं:

> *दोनों पक्षकारों द्वारा संदर्भित कई उदाहरणों वाले अभिवचनों से, यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षकारों द्वारा विभिन्न तथ्यात्मक पहलू पर आरोप लगाए गए और अस्वीकार किए गए हैं, और दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार किए गए और साथ ही विवादित तथ्यों से निकाले गए तर्क और निष्कर्ष बिल्कुल विपरीत हैं और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह आवश्यक और उचित है कि पक्षकारों को अपनी दलीलों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रतिपरीक्षा का सामना करने का अवसर दिया जाए। मेरी*

सुविचारित राय में पक्षकारों को ऐसा करने का अवसर दिए बिना, एक या दूसरे के पक्ष में निष्कर्ष निकालना अत्यधिक अनुचित होगा। विस्तृत और विवादित तथ्यात्मक मैट्रिक्स के लिए दोनों पक्षकारों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और मेरे विचार में इसकी अनुपस्थिति में, संशोधन और बदलाव करने के ऐसे महत्वपूर्ण पहलू पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, विशेष रूप से अमेरिका में रहने के संदर्भ में, क्योंकि यह मुख्य रूप से पक्षकारों के अधिकारों से अधिक बच्चे के कल्याण से संबंधित है।

26. चूँकि याचिकाकर्ता ने जोरदार आग्रह किया है कि पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देना पूरी तरह से अनावश्यक था और इसलिए, पूरी तरह से विकृत थे, इसलिए मेरे विचार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि क्या विद्वान कुटुम्ब न्यायालय द्वारा पक्षकारों को उनकी दलीलों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित था। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, साक्ष्य दर्ज करने के लिए विद्वान कुटुम्ब न्यायालय का यह निर्देश इस आधार पर आधारित है कि विभिन्न विवादित तथ्यात्मक पहलू थे जिन्हें निर्धारित करने की आवश्यकता थी। जबकि याचिकाकर्ता की दलील यह है कि कोई विवादित तथ्य नहीं थे, प्रत्यर्थी **ने** अन्यथा तर्क दिया है।

27. इन विरोधी अभिवचनों की सराहना करने के लिए, शुरूआत में ही, उन तथ्यों पर ध्यान देना उचित हो सकता है जिस पर पक्षकारों में मतभेद नहीं हैं। यह तथ्य कि दोनों पक्षकारों ने स्वेच्छा से 25.05.2019 को समझौता करार किया, जिसके तहत उनके बीच पारस्परिक रूप से सहमति हुई कि बेटी की संरक्षण याचिकाकर्ता के पास रहेगी, दोनों पक्षकारों द्वारा इसे स्वीकार किया

गया था। नतीजतन, इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि 2018 में प्रारंभिक समझौते के समय और 2019 में बाद के समझौते के समय, प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता को अपनी बेटी की प्राथमिक देखभालकर्ता होने के लिए सहमत था। प्रत्यर्थी इस बात पर भी विवाद नहीं करता है कि बेटी अपने जन्म के समय से ही याचिकाकर्ता की संरक्षण में है और याचिकाकर्ता द्वारा संशोधन और रहने की माँग करने वाले आवेदन दायर करने से पहले, प्रत्यर्थी ने कभी भी इस मुलाकात व्यवस्था में कोई संशोधन नहीं किया था, जो उसे रात भर की सीमित मुलाकात का अधिकार प्रदान करता था। यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2021 में अमेरिका के निवासी डॉ. रितेश कनोत्रा से शादी की और नाबालिग बच्चे के साथ अपने पति के पास रहने के लिए अमेरिका में बसना चाहती है, पर भी विवाद नहीं है।

28. डॉ. कनोत्रा के साथ अपनी शादी होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने जून, 2021 में मुलाकात करने के अधिकारों में संशोधन के लिए आवेदन दायर किया ताकि बच्चे के साथ अमेरिका में बसा जा सके। इसके बाद प्रत्यर्थी ने भी अक्टूबर, 2021 में एक आवेदन दायर किया जिसमें बच्ची की संरक्षण उसे दिए जाने की प्रार्थना करते हुए मिलने के अधिकारों में संशोधन की माँग की गई थी। हालाँकि, जो सामने आया वह यह है कि संशोधन और बसने की माँग करने वाले याचिकाकर्ता के आवेदन का पूरा आधार यह है कि अब जब उसकी शादी अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर से हुई है, तो उसे अमेरिका जाने की

आवश्यकता है। उसका मामला यह है कि छोटा बच्चा जन्म से ही उसकी विशेष देखभाल में रहा है और इसलिए, यह बच्चे के हित में होगा कि वह उसके साथ अमेरिका चले जाए। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पूरी तरह से अमेरिका में स्थायी रूप से रहने वाले डॉक्टर के साथ उसकी शादी के परिणामस्वरूप बदली हुई परिस्थितियों पर आधारित है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संशोधन के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना प्रत्यर्थी के किसी भी कृत्य पर आधारित नहीं है और इसलिए उसकी प्रार्थना प्रत्यर्थी के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप पर आधारित नहीं है।

29. दूसरी ओर, भले ही प्रत्यर्थी ने मुलाकात के अधिकारों को बढ़ाने के लिए अपने आवेदन में याचिकाकर्ता के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए हों, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि यह आवेदन 27.10.2021 को दायर किया गया था, यानी याचिकाकर्ता द्वारा बसने की माँग के लगभग पांच महीने बाद। इसलिए इन आरोपों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए और इन्हें आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अन्यथा भी, अधिकांश आरोप सितंबर, 2018 से फरवरी, 2019 के बीच की अवधि से संबंधित थे, जिसके बाद दोनों पक्षकारों ने पारस्परिक रूप से 25.05.2019 को समझौता किया था। इसलिए, मेरे विचार में, इन आरोपों का इस प्रश्न पर कोई असर नहीं होगा कि संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।

30. इस स्तर पर, समझौता करार की प्रासंगिक शर्तों पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। समझौते का पैरा 9, जिसमें दोनों पक्षकार मुलाकात की शर्तों पर सहमत हुए थे, निम्नानुसार है:

> *पक्षकारों के बीच आगे यह सहमति बनी है कि बच्चे का संरक्षण/देखभाल माँ, आकृति के पास रहेगी और पति याचिकाकर्ता को मिलने का अधिकार निम्नलिखित होगाः*
>
> *(क) पति को बच्चे अनीशा से महीने में दो बार, अर्थात महीने के पहले रविवार को पांच घंटे के लिए, यानी पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक मिलेगा। यह भी सहमति हुई कि बच्चे को पिता/याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों द्वारा निर्धारित समय पर ले जाया जाएगा और याचिकाकर्ता/पति के परिवार के सदस्यों के द्वारा वापस छोड़ दिया जाएगा।*
> *(ख) चौथे शनिवार को याचिकाकर्ता/परिवार के सदस्य बच्चे को अपराह्न 6:00 बजे ले जाएँगे और याचिकाकर्ता/पिता बच्चे को चौथे रविवार (अगले दिन) को प्रत्यर्थी/माँ के घर अपराह्न 6:00 बजे वापस छोड़ देंगे।*
> *(ग) यह भी सहमति हुई कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान, याचिकाकर्ता को बच्चे से मिलने का अधिकार पांच दिनों के लिए और सर्दियों की छुट्टियों के दौरान तीन दिनों के लिए होगा। पक्षकार ईमेल/वॉट्सऐप संदेशों के आदान-प्रदान के द्वारा छुट्टियों के दौरान मिलने के दिनों का फैसला करेंगे।*
> *(घ) यह सहमति हुई कि याचिकाकर्ता को बच्चे के जन्मदिन पर पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे के बीच तीन घंटे के लिए मिलने का अधिकार होगा।*
> *(ङ) यह भी सहमति हुई कि याचिकाकर्ता को दिवाली के त्योहार पर पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे के बीच तीन घंटे के लिए बच्चे से मिलने का अधिकार होगा।*

31. उपरोक्त के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने मई, 2019 में विशेष रूप से सहमति व्यक्त की थी कि बच्चे का संरक्षण याचिकाकर्ता/माँ के

पास रहेगी और प्रत्यर्थी/पिता महीने में दो बार बच्चे से मिलने का हकदार होगा। इन मासिक मुलाकातों में से प्रत्येक महीने के चौथे शनिवार को प्रत्यर्थी और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहेगी। इसके अलावा, प्रत्यर्थी को गर्मी की छुट्टियों में पांच दिनों और सर्दियों की छुट्टियों में तीन दिनों के लिए बच्चे के संरक्षण का भी अधिकार होगा।

32. उस अवधि को छोड़कर जब महामारी अपने चरम पर थी, यह व्यवस्था पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से निर्बाध रूप से जारी है, इस अवधि के दौरान बच्चा दो साल के शिशु से छह साल के बच्चे में विकसित हो गया है, जिसका अपना दिमाग है। प्रत्यर्थी द्वारा कोई आरोप नहीं लगाया गया है कि बच्चा नाखुश है या उसने कभी उससे शिकायत नहीं की कि वह याचिकाकर्ता के साथ नहीं रहना चाहती है। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेष रूप से जब यह पक्षकारों का सामान्य मामला है कि प्रत्यर्थी नियमित रूप से बच्चे के साथ या तो शारीरिक रूप से या वीडियो कॉल द्वारा बातचीत कर रहा है। बच्चे की संरक्षण की माँग करने के लिए प्रत्यर्थी का मुख्य अभिवचनों में से एक यह है कि याचिकाकर्ता ने कुछ अवसरों पर अपने भावी पति डॉ. कनोत्रा से मिलने के लिए बच्चे को अपने माता-पिता के पास छोड़ दिया था। उल्लेखनीय बात यह है कि याचिकाकर्ता ने भी इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया है कि कुछ मौकों पर, उसने नाबालिग बच्चे को अपने माता-पिता के पास छोड़ दिया था, लेकिन उसने बताया कि इस अवधि के दौरान, बच्चे की

अच्छी तरह देखभाल की जा रही थी क्योंकि उसके साथ-साथ न केवल उसके मामा-मामी रहते थे, बल्कि उसके दो ममरे भाई भी रहते थे। इन परिस्थितियों में, मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि कौन से वे विवादित तथ्य हैं जो संशोधन के मुद्दे को निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक होंगे, जिसे साक्ष्य द्वारा साबित करने की आवश्यकता है। यह न्यायालय इस बात को समझने में विफल रहा है कि पक्षकारों से और किस साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकती है या प्रतिपरीक्षा द्वारा क्या फलदायी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर के साथ अपनी शादी के तथ्य और नाबालिग बेटी की आवश्यकता के आधार पर किया है, जन्म के बाद से वह उसके साथ रहती आई है, जिनमें से किसी भी तथ्य का प्रत्यर्थी द्वारा खंडन नहीं किया गया है। इसलिए, मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई दुविधा नहीं है कि आवेदनों के न्यायनिर्णयन के लिए किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी।

33. मैंने ***चिंतामन सदाशिव वैशम्पायन (पूर्वोक्त), अयुबखान नूरखान पठान (पूर्वोक्त), सुमेधा नागपाल (पूर्वोक्त), के.एस. वेंकट राजा (पूर्वोक्त) और अक्कमहादेवी (पूर्वोक्त) के*** फैसलों पर भी विचार किया है जिस पर प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया लेकिन पाया कि वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि इस प्रतिपादना के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि विवादित तथ्यों/मुद्दों के न्यायनिर्णयन के लिए,

साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार पक्षकारों का एक मूल्यवान अधिकार है जिसे कम नहीं किया जाना चाहिए, वर्तमान मामले में, मैं पाता हूँ कि कोई भी विवादित तथ्य नहीं हैं। इसलिए ये निर्णय प्रत्यर्थी के मामले को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाते हैं।

34. ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस तथ्य की अनदेखी की है कि पारिवारिक मामले, विशेष रूप से जहां नाबालिग बच्चे शामिल हैं, पर तेजी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 10(3) पर भरोसा करने में सही है, जिसमें यह प्रावधान है कि विद्वान कुटुम्ब न्यायालय सच्चाई तक पहुंचने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है और सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित साक्ष्य के सख्त नियमों से बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। मेरे विचार में, वर्तमान जैसे मामले में, जहां कुटुम्ब न्यायालय को एक नाबालिग बच्चे के कल्याण का आकलन करने की आवश्यकता है, जब तक कि तथ्य के वास्तविक और पर्याप्त विवादित प्रश्न न हों, न्यायालय को जहां तक संभव हो संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह तथ्य कि दोनों पक्षकारों ने आपसी समझौता किया, जिसके तहत वे नाबालिग बेटी का संरक्षण माँ को देने और पिता के साथ प्रत्येक महीने में एक दिन रात भर और गर्मी की छुट्टियों में पांच दिन और सर्दियों की छुट्टियों में तीन दिन मिलने

देने के लिए सहमत हुए, यह स्पष्ट करता है कि तथ्यों के बारे में कोई विवादित प्रश्न नहीं थे, जिसके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। पक्षकारों के इस समझौते पर पहुंचने के बाद, जहां तक बच्चे का संबंध है, कुछ भी सामग्री नहीं बदली है, सिवाय इसके कि दोनों पक्षकारों ने अब पुनर्विवाह कर लिया है। आक्षेपित आदेश, जहाँ तक यह अभिनिर्धारित करता है कि पक्षकारों द्वारा दायर आवेदनों के न्यायनिर्णयन के लिए, उनके लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना और प्रतिपरीक्षा का सामना करना आवश्यक था, इसलिए असंधार्य है।

35. यह पता चलने के बाद कि दोनों पक्षकारों के आवेदनों पर पहले से ही दर्ज सामग्री के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है, आगे क्या? क्या इस न्यायालय को आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए मामले को विद्वान कुटुम्ब न्यायालय को वापस भेजना चाहिए या क्या इस न्यायालय को इन आवेदनों पर निर्णय लेने का कार्य स्वयं करना चाहिए। सुश्री लूथरा ने जोरदार आग्रह किया है कि यदि यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आवेदनों पर निर्णय लेता है, तो यह पक्षकारों को विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के उनके मूल्यवान अधिकार से वंचित कर देगा। भले ही प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह अभिवचन पहली नजर में आकर्षक प्रतीत होती है, लेकिन यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं

कर सकता है कि याचिकाकर्ता ने अप्रैल, 2021 में डॉ. कनोत्रा से शादी की और जून, 2021 में रहने के लिए आवेदन दायर किया, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, वह अभी भी गुणागुण के आधार पर अपने आवेदन के न्यायनिर्णयन की प्रतीक्षा कर रही है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जिसमें न्यायालय पूरी तरह से अलग प्रकार के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है और न केवल पति और पत्नी के बीच अब बिगड़ गए कड़वे संबंधों से जुड़े मामलों का निपटान कर रहा है, बल्कि माता-पिता के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए नाबालिग बच्चों के कल्याण के बारे में भी प्रश्न उठा रहा है। इसलिए कुटुम्ब न्यायालयों के समक्ष मुद्दों पर शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि संरक्षण के मामलों के न्यायनिर्णयन में कोई भी देरी स्वाभाविक रूप से बच्चे के लिए आघातकारी होगी। वर्तमान मामले में, न्यायालय को केवल यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या माँ, जो अपने पुनर्विवाह के कारण अमेरिका में रहना चाहती है, उसे प्रत्यर्थी/पिता से मिलने के अधिकारों को संशोधित करके अपनी बेटी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखने पर मेरा मानना है कि यह वास्तव में बच्चे के कल्याण के लिए होगा कि आवेदनों पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। इसलिए, यह न्यायालय पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर निर्णय लेने का कार्य अपने हाथ में ले रहा है, एक याचिकाकर्ता/माँ द्वारा संरक्षण आदेश में संशोधन की माँग

करने के लिए ताकि वह बच्चे के साथ अमेरिका में रह सके और दो प्रत्यर्थी पिता द्वारा, जिसमें उसने न केवल मौजूदा मुलाकात समझौते को लागू करने की बल्कि नाबालिग बच्चे की संरक्षण की भी माँग की है।

36. इन आवेदनों के द्वारा पक्षकारों द्वारा माँगी गई प्रार्थनाओं की सराहना करने के लिए, उस आक्षेपित आदेश का उल्लेख करना उचित हो सकता है जिसमें विद्वान कुटुम्ब न्यायालय ने पक्षकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कहा था कि तीनों आवेदन संरक्षण आदेश से संबंधित थे, जो उनके बीच हुए आपसी समझौते पर आधारित था। आक्षेपित आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है -

> *"वर्तमान मामले में एकमात्र विवाद बच्चे के संरक्षण से संबंधित है, विशेष रूप से इस पृष्ठभूमि में कि संरक्षक माता-पिता यानी माँ अब विवाहित हैं और पति अमेरिका में एक डॉक्टर है और वह अमेरिका में रहना चाहती है और तदनुसार गैर-संरक्षक पिता यानी पिता की बच्चे के साथ मुलाकात करने के वर्तमान व्यवस्था में संशोधन की माँग की है, जो आपसी समझौते के अनुसार हुआ था और आपसी सहमति से तलाक की माँग करते समय उस पर कार्रवाई की गई थी और पारस्परिक सहमति से विवाह को भंग करने वाले डिक्री पारित करते समय आदेश पारित किया गया था। तत्पश्चात प्रत्यर्थी/पिता ने भी इस पृष्ठभूमि में बच्चे की संरक्षण की माँग की है कि पिता के साथ न्यूनतम प्रकृति के साथ संरक्षण व्यवस्था के बावजूद आदेश का उल्लंघन हुआ है। यह तर्क दिया गया कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अदालत के निर्देश के बावजूद संरक्षक माता-पिता यानी माँ ने बातचीत की अनुमति देने से इनकार कर दिया और केवल जब उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो वीडियो कॉल व शारीरिक संपर्क के माध्यम से बातचीत पुनः शुरू हुई।"*

37. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि भले ही विद्वान कुटुम्ब न्यायालय तीन आवेदनों पर विचार कर रहा था, लेकिन एकमात्र प्रश्न जो उसे निर्धारित करने की आवश्यकता थी वह यह थी कि क्या संरक्षण आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता ने मुख्य रूप से आग्रह किया है कि अब जब उसने पुनर्विवाह कर लिया है और उसका पति अमेरिका में बस गया है, तो उसके लिए अमेरिका में अपने पति के साथ रहना आवश्यक है ताकि वह अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा कर सके। इसके अलावा, चूँकि वह एक योग्य रेडियोलॉजिस्ट हैं, इसलिए वह अमेरिका में पेशे से संबंधित अवसरों का पता लगाना चाहेंगी। एक संरक्षक माता-पिता और प्राथमिक देखभालकर्ता होने के नाते, जिसने उसके जन्म के बाद से ही अकेले बच्चे की देखभाल कर रहा है, यह उस बच्चे के हित और कल्याण में होगा जो मुश्किल से छह साल का है, कि वह याचिकाकर्ता के साथ अमेरिका में रहे। यह भी आग्रह किया गया है कि यह ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी को बच्चे के साथ बातचीत करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, याचिकाकर्ता छुट्टियों के दौरान बच्चे को भारत लाने के लिए तैयार है ताकि प्रत्यर्थी को सहमत मासिक बातचीत और मुलाकात के बदले में तीन से चार सप्ताह के लिए विशेष संरक्षण दी जा सके।

38. दूसरी ओर, यह प्रत्यर्थी का मामला यह है कि बच्चे की कम उम्र को देखते हुए, भले ही वह याचिकाकर्ता को प्राथमिक देखभालकर्ता होने के लिए

सहमत था, वह इस शर्त के अधीन था कि उसे बच्चे के साथ नियमित बातचीत करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वह उसके साथ एक अच्छा संबंध विकसित कर सके। याचिकाकर्ता, स्वेच्छा से इस व्यवस्था के लिए सहमत होने के बाद, जिसके अनुसार प्रत्यर्थी हर महीने के पहले रविवार को नियमित रूप से मुलाकात करने और हर महीने के चौथे शनिवार को रात भर रखने का हकदार है, अब इस व्यवस्था से केवल इसलिए बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसने अमेरिका में बसे एक डॉक्टर से शादी कर ली है। मौजूदा व्यवस्था में कोई भी बदलाव न केवल प्रत्यर्थी/पिता के हित के खिलाफ होगा, बल्कि उस बच्चे के भलाई के खिलाफ भी होगा जो अपने बढ़ते वर्षों में अपने पिता की देखभाल और मार्गदर्शन से वंचित रहेगा। यह भी आग्रह किया गया है कि डॉ. रितेश कनोत्रा के साथ याचिकाकर्ता की शादी एक पूर्व-नियोजित व्यवस्था का परिणाम थी क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से उसके साथ नियमित संपर्क में था और वास्तव में दोनों पक्षकारों के बीच वैवाहिक कलह का एक कारण यह भी था। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया है कि याचिकाकर्ता एक लापरवाह माँ है जो बच्चे को अपने बूढ़े माता-पिता के पास छोड़कर डॉ. कनोत्रा से मिलने के लिए बार-बार अमेरिका की यात्रा करती थी। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि बच्चे को अमेरिका में रहने देने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाए।

39. पक्षकारों की इन प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, पहले पक्षकारों द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वही नाबालिग बच्चों की संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए मापदंडों को निर्धारित करता है।

40. चूँकि प्रत्यर्थी ने जोरदार आग्रह किया है कि मौजूदा संरक्षण व्यवस्था आपसी समझौते पर आधारित है, इसलिए इसे अब बदला नहीं जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा भरोसा किए गए ***विक्रम वीर वोहरा (पूर्वोक्त)*** में निर्णय का उल्लेख करना उचित हो सकता है। उक्त निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने माँ के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, जो संरक्षक माता-पिता थीं और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहना चाहती थीं, इस बात पर जोर दिया कि संरक्षण आदेश, भले ही वे सहमति आदेश हों, को हमेशा अंतर्वर्ती आदेश माना जाता है और बच्चे के भलाई के लिए हमेशा बदला जा सकता है। उक्त निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार हैं:

> *12. बच्चे की संरक्षण से संबंधित मामले में, इस न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि वह देखभाल और स्नेह की प्रकृति पर विचार करने में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे से निपट रहा है जिसे एक बच्चे को उसके जीवन के बढ़ते चरणों में चाहिए। यही कारण है कि संरक्षण आदेशों को हमेशा अंतर्वर्ती आदेश माना जाता है और ऐसी कार्यवाही की प्रकृति से संरक्षण आदेशों को कठोर और अंतिम नहीं बनाया जा सकता है। वे बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित और ढाले जाने में सक्षम हैं।*
> *13. रोजी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल [(1973) 1 एस.सी.सी. 840] मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने कहा कि*

नाबालिगों के संरक्षण से संबंधित सभी आदेशों को अस्थायी आदेश माना जाता है। विद्वान न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया कि समय बीतने के साथ, न्यायालय नाबालिग बच्चे के हित में आदेश में संशोधन करने का हकदार है। न्यायालय ने यहाँ तक कहा कि भले ही आदेश सहमति पर आधारित हों, लेकिन बच्चे के कल्याण के लिए आवश्यक होने पर उन आदेशों में बदलाव भी किया जा सकता है।

* * * * *

18. अब बच्चे को ऑस्ट्रेलिया ले जाने और उसके परिणामस्वरूप पिता के मुलाक़ात के अधिकारों में बदलाव के प्रश्न पर आते हुए, इस अदालत ने पाया कि प्रत्यर्थी माँ को ऑस्ट्रेलिया में नौकरी का बेहतर अवसर मिल रहा है। उसके व्यक्तित्व पर उसकी स्वत्व अधिकार को अदालत द्वारा बच्चे के संरक्षण के पूर्व आदेश के आधार पर कम नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने का अधिकार है। वास्तव में विकास करने का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। प्रत्यर्थी माँ को अपने बच्चे और अपने करियर के बीच चयन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यह स्पष्ट है कि बच्चा उसे बहुत प्रिय है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि बच्चे को अपने क्षमता को विकसित करने और अंततः एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उचित शिक्षा और प्रशिक्षण मिले। यदि बच्चे के संरक्षण से उसे वंचित कर दिया जाता है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में अपना करियर बनाने में सक्षम नहीं हो पाती और यह उसके करियर के विकास या बच्चे की भविष्य की संभावनाओं के लिए अनुकूल नहीं होता। बच्चे को उसकी माँ से अलग करना दोनों के लिए विनाशकारी होगा।

19. जहाँ तक पिता का संबंध है, वह पहले से ही भारत में स्थापित हैं और वह आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं। उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों में उनके मिलने के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। उनके अधिकार परिवर्तित रहे हैं लेकिन उसकी पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की गई है। अपीलकर्ता पिता इतने वर्षों तक बच्चे के बिना रहे और उन्हें इसकी आदत हो गई।

41. अब मैं ***रोहित थमन्ना (पूर्वोक्त)*** के निर्णय का उल्लेख कर सकता हूँ, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामलों में, प्राथमिक प्रश्न यह है कि संबंधित बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामलों में, पक्षकारों के अभिवचनों और शपथपत्रों में जवाबी आरोपों से निपटना हमेशा आवश्यक नहीं हो सकता है। इस निर्णय के पैरा 8 में उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

> *8. प्रारंभ में हम यह कह सकते हैं कि किसी बच्चे के संरक्षण के प्रश्न से संबंधित मामले में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि प्रश्न 'बालक की इच्छा/अभिलाषा क्या है' इस प्रश्न से भिन्न और अलग है कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा'। निश्चित रूप से, बच्चे की इच्छा/अभिलाषा का पता बातचीत के द्वारा लगाया जा सकता है, लेकिन फिर, यह प्रश्न कि 'बच्चे के सर्वोत्तम हित में क्या होगा' सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत द्वारा तय किया जाना है। जब दम्पति आपस में झगड़ते हैं और आख़ीरी दाँव के रूप में अपने-अपने रास्ते अलग करना चाहते हैं तो वे एक-दूसरे के खिलाफ अति गंभीर आरोप लगा सकते हैं ताकि दूसरे को बच्चे के संरक्षण के लिए अयोग्य दिखाया जा सके। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि एक नाबालिग बच्चे के संरक्षण के दावे पर विचार करने के लिए, जब तक कि बहुत गंभीर, सिद्ध आचरण जो उनमें से एक को संबंधित बच्चे के संरक्षण करने के लिए दावा करने के योग्य नहीं बनाता है, प्रश्न का निर्णय केवल इस प्रश्न को देखते हुए किया जा सकता है और किया जाएगा कि 'संबंधित बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या होगा'। दूसरे शब्दों में, बच्चे के कल्याण का विचार सर्वोपरि होना चाहिए। मामले को उस दृष्टिकोण से देखने पर हम सोचते हैं कि उसके संबंधित अभिवचनों और शपथपत्रों में सभी तर्कों और आरोपों की चर्चा करना और उसका निपटान करना बिल्कुल अनावश्यक है।*

42. इस स्तर पर, ***अनुराधा शर्मा (पूर्वोक्त)*** मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक निर्णय का भी संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें अदालत ने एक माँ के अनुरोध पर विचार करते हुए, जो अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने के लिए पोलैंड में रहना चाहती थी, इस बात पर प्रकाश डाला कि इस अनुरोध को तय करने के लिए प्राथमिक विचार बच्चे का कल्याण होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि भले ही रहने की अनुमति दी जानी थी, लेकिन गैर-संरक्षक माता-पिता के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। उक्त निर्णय का पैराग्राफ 29, 30, 33, 34 निम्नानुसार है:

> *29. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नाबालिग लड़की की संरक्षण माँ के पास होती है, जो स्वाभाविक अभिभावक है और उसकी उम्र को देखते हुए, लड़की को अपनी माँ के साथ जाना चाहिए, विशेष रूप से जब यह मामला याचिकाकर्ता का है कि उसने पति से अलग होने पर अकेले ही बच्चे का पालन-पोषण किया है।*
>
> *30. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील है, अल्पायु अक्षिता के प्रति माता-पिता दोनों के गहरे प्यार और स्नेह को देखते हुए, जिसके एक या दो दिनों में 9 साल की होने की संभावना है। पिता निश्चित अंतराल पर आभासी और शारीरिक रूप से बच्चे की पहुँच का आनंद ले रहे हैं। वह स्वाभाविक रूप से बच्चे के कल्याण के बारे में चिंतित है और उसकी एकमात्र चिंता यह है कि अगर उसे पोलैंड ले जाया जाता है तो दोनों के बीच का संबंध टूट जाएगा।*
>
> * * * * *
>
> *33. आवश्यक रूप से, दोनों पक्षकारों के हितों के बीच एक संतुलन बनाना होगा और बच्चे के कल्याण पर सर्वोपरि विचार करना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माता-पिता के बीच टकराव की स्थिति में बच्चे में सुरक्षा की भावना हो और यह हमेशा बच्चे के हित में है कि जब*

तक वह बड़ा हो, तब तक माता-पिता दोनों की उपस्थिति हो, लेकिन यहां एक ऐसी स्थिति है जिसमें माता-पिता के बीच टकराव है और बच्चा माँ के साथ रहता है और पिता को सीमित पहुंच प्रदान की जाती है, जिसका उसे गुणात्मक रूप से लाभ उठाना चाहिए। याचिकाकर्ता बच्चे की माँ है और वह बच्चे के जन्म से है लगातार उसके साथ रही है और हालांकि वह एक कामकाजी महिला है, उसने अपने काम और बच्चे की देखभाल और स्नेह के बीच संतुलन बनाया है और यह सुनिश्चित किया है कि उसे अच्छा परवरिश मिले। पति द्वारा सुझाया गया विकल्प कि बच्चे को उसके पास छोड़ दिया जाना चाहिए और उसका परिवार उसकी देखभाल करेगा, व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि छोटी लड़की हमेशा अपनी माँ के साथ रहती है, कुछ घंटों को छोड़कर, जब वह विशेष रूप से अपने पिता या उसके परिवार के साथ थी। एक बात स्पष्ट है कि लड़की को याचिकाकर्ता-माँ से अलग नहीं किया जा सकता है।

34. हालाँकि, साथ ही, इस तथ्य के प्रति भी सचेत थी कि बच्चे ने पिता के साथ एक मजबूत संबंध विकसित किया है और इसे पोषित करने और जारी रखने की आवश्यकता है, भले ही बच्चा अपनी माँ के साथ उसकी बेहतर संभावनाओं के लिए पोलैंड जाए, जिसका लाभ उठाने से उसे रोका नहीं जा सकता है।

43. कुछ निर्णयों पर ध्यान देने के बाद, जिसमें न्यायालयों ने बसने के लिए संरक्षक माता-पिता के समान आवेदनों पर विचार किया है, मैं अब वर्तमान मामले के तथ्यों की ओर रुख कर सकता हूँ। प्रारंभ में ही, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत, जिस पर पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत थी, प्रत्यर्थी 20 दिन रात में मुलाकात करने का हकदार था, जिसमें हर महीने के चौथे शनिवार को रात भर रहने, गर्मी की छुट्टियों के दौरान पांच बार रात में मुलाकात करने और सर्दियों की छुट्टियों के

दौरान तीन बार। यह हर महीने के पहले रविवार को पांच घंटे की मासिक 'दिन की मुलाकात' के अतिरिक्त था। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि नाबालिग बच्चे का उससे गहरा लगाव है क्योंकि वह जन्म से ही याचिकाकर्ता के साथ रह रही है और बाल्य काल से ही उससे सारा प्यार और स्नेह प्राप्त कर रही है। बच्चा जीवन के हर क्षेत्र में न केवल अपनी माँ से प्यार, स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए बड़ा हुआ है, बल्कि कोविड महामारी के चरम के दौरान को छोड़कर, उसे कभी भी अपने पिता के साथ समय बिताने के अवसर से वंचित नहीं किया गया है। महामारी के दौरान भी, वह नियमित रूप से वीडियो कॉल द्वारा पिता के साथ बातचीत करती थी। इसलिए, याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि रात भर रहने की मौजूदा व्यवस्था के इन 20 दिनों की भरपाई प्रत्यर्थी को आसानी से उसकी भारत की वार्षिक यात्राओं पर बच्चे की विशेष संरक्षण प्रदान करके की जा सकती है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी बच्चे के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकता है, जब भी वह चाहे, वीडियो कॉल द्वारा, जिसका आग्रह किया गया है, कोविड महामारी के युग के बाद बातचीत के एक सामान्य तरीके के रूप में उभरा है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी के मिलने के अधिकारों में कटौती करना चाहता है, जो एक पिता के रूप में बच्चे के साथ अपना संबंध बनाए रखने का हकदार है, बल्कि केवल मिलने की शर्तों में कुछ संशोधन की माँग कर रहा है ताकि वह अपने

विवाहित जीवन और अपनी बेटी, जिसे वह बहुत प्यार करती है, के बीच चयन करने के लिए मजबूर न हो।

44. प्रत्यर्थी की विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री लूथरा ने जोरदार आग्रह किया है कि नाबालिग बच्चे के लिए अपने जीवन के इस प्रारंभिक और संस्कारग्राही चरण के दौरान अपने पिता की निरंतर देखभाल और मार्गदर्शन करना महत्वपूर्ण है। यह उनका अभिवचन कि पिता एक सांता क्लॉज़ की तरह नहीं है जिसके अधिकारों को केवल साल में एक बार बच्चे से मिलने की अनुमति देकर पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जा सकता है। इस कम उम्र में नाबालिग बच्चे को पिता के साथ नियमित बातचीत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, जो उसके संबंध को मजबूत करने के लिए अनिवार्य है। इसलिए यह आग्रह किया गया है कि बच्चे को इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

45. पक्षकारों की इन प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, मैं सुश्री लूथरा से सहमत हूँ कि पिता, भले ही वह एक गैर-संरक्षक माता-पिता हों, बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और किसी भी नाबालिग बच्चे को उसके माता-पिता के स्पर्श और प्रभाव से अछूता नहीं होना चाहिए क्योंकि वे दोनों बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस संबंध में, ***रुचि माजू (पूर्वोक्त)*** में अपने निर्णय के पैरा 73 में

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है, जिस पर प्रत्यर्थी ने भरोसा किया था। वह निम्नानुसार है:

> *73. यह महत्वपूर्ण है कि नाबालिग के जीवन के इस प्रारंभिक और संस्कारग्राही चरण में उसके पिता की देखभाल और मार्गदर्शन हो। न ही जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए उसके पालन-पोषण और संवारने में पिता की भूमिका को कमतर किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पिता से मिलने का अधिकार प्रदान करें जो दोनों को संपर्क में रहने और एक-दूसरे के साथ हँसी-खुशी, सीखने और आनंद के क्षणों को साझा करने में सक्षम बनाएगा। चूँकि प्रत्यर्थी किसी अन्य महादेश में रह रहा है, इसलिए इस तरह का संपर्क स्पष्ट कारणों से नहीं हो सकता है जितना कि वे एक ही शहर में होते। लेकिन दोनों को अलग करने वाली निषिद्ध दूरी दूरसंचार के आधुनिक तकनीक के कारण कम हो हुई है।*

46. इस प्रकार, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक पिता के रूप में प्रत्यर्थी को नाबालिग बच्चे के साथ बार-बार बातचीत करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्या इसका मतलब यह है कि यह अधिकार केवल शारीरिक मुलाकातों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, यह इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न है। एक सहायक प्रश्न यह भी है कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने अमेरिका में एक डॉक्टर से शादी की है, क्या उसे केवल बच्चे का संरक्षण छोड़ने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्थी हर महीने दो बार बच्चे से शारीरिक रूप से मिलना चाहता है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि बच्चा, जो कुछ हफ्तों में छह साल का हो जाएगा, याचिकाकर्ता द्वारा अकेले ही पाला गया है और जाहिर तौर पर

खुश मनःस्थिति में है। यह प्रत्यर्थी का मामला भी नहीं है कि उसने कभी माँ द्वारा उपेक्षित होने की शिकायत की हो। माँ को भी इस बात का श्रेय जाता है, बच्चे ने भी कभी भी पिता के लिए कोई नापसंदगी नहीं व्यक्त की है। सौभाग्य से, बच्चे में, जैसा कि अक्सर संरक्षण विवादों में पाया जाता है, पिता के प्रति कोई नापसंदगी की भावना विकसित नहीं हुई है। यह, मेरे विचार में, यह दिखाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि याचिकाकर्ता, जिसे प्रत्यर्थी की सहमति से, मई, 2019 में संरक्षण माता-पिता बनाया गया था, जब बच्चा मुश्किल से दो साल का था, ने बच्चे को प्यार और देखभाल के साथ पाला है।

47. हालाँकि, मुझे सुश्री लूथरा से सहमत होने में कोई झिझक नहीं है कि बच्चे को पिता के साथ नियमित रूप से बातचीत करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अब इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या बच्चे और पिता के इस अधिकार की रक्षा केवल बच्चे को भारत में रहने के लिए मजबूर करके की जा सकती है, जबकि उसकी माँ अमेरिका में बस जाती है। मेरे विचार में इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। आज तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि अलग-अलग देशों या महादेशों में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच नियमित बातचीत वीडियो कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आसानी से किया जा सकता है। वास्तव में, पिछले तीन वर्षों में, जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, वीडियो कॉल के द्वारा बातचीत करना

एक नया मानदंड बन गया है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि आज जब अदालतें पूरी तरह से शारीरिक रूप से काम कर रही हैं, तब भी वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। यह केवल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण हुआ है।

48. प्रत्यर्थी, जिसने स्वेच्छा से याचिकाकर्ता को दो साल की उम्र से ही बच्चे की देखभाल करने की अनुमति दी थी और हर महीने दो बार मिलने से संतुष्ट था, जिसमें से एक रात भर के लिए था, अब उसे यह आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि माँ अमेरिका में बसना चाहती है, उसे बच्चे को उसके संरक्षण में छोड़ देना चाहिए। मेरे विचार में, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बच्चा विशेष रूप से माँ की संरक्षण में रहा है, जिससे उसे बेहद लगाव बताया गया है, यह वास्तव में उसके कल्याण में होगा कि वह उसी के साथ रहे। इस स्तर पर बच्चे का अपनी माँ से अलग होना उसके लिए अनुचित चिंता का कारण बन सकता है जिससे निश्चित रूप से बचने की आवश्यकता है। दूसरी ओर, अमेरिका में रहते हुए भी, बच्चा अपने पिता के साथ नियमित रूप से वीडियो कॉल द्वारा बातचीत करने की स्थिति में होगा, यहां तक कि दैनिक आधार पर भी, अगर वह चाहे। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक पिता के रूप में बच्चे के साथ नियमित रूप से शारीरिक रूप से बातचीत करने का प्रत्यर्थी का अधिकार प्रभावित होगा, अगर बच्चे को अपनी माँ के साथ अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाती है, तो भी मेरा विचार है कि यह

अभी भी बच्चे के कल्याण में होगा कि वह माँ की संरक्षण में रहे। पिता के अधिकारों में इस कटौती की भरपाई काफी हद तक उसे वीडियो कॉल द्वारा बातचीत करने की अनुमति देकर और छुट्टियों के दौरान उसे विशेष संरक्षण प्रदान करके की जा सकती है।

49. मैं यह भी नोट कर सकता हूँ कि हालांकि यह न्यायालय, एक स्तर पर, नाबालिग बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए इच्छुक था, उसकी कम उम्र और प्रत्यर्थी द्वारा तीव्र विरोध को ध्यान में रखते हुए, बच्चे को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया था। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वर्तमान मामले में, इस न्यायालय के पास न केवल याचिकाकर्ता, उसके माता-पिता और उसके वर्तमान पति का बयान दर्ज करने का अवसर था, बल्कि प्रत्यर्थी और उसकी माँ का भी बयान दर्ज करने का अवसर था। प्रत्यर्थी की वर्तमान पत्नी का बयान दर्ज नहीं किया जा सका क्योंकि कहा गया कि वह अब उसके साथ नहीं रह रही है। भले ही, आदेश X नियम 2 सी.पी.सी. के तहत दर्ज किए गए बयान, आदेश XVIII सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार शपथ के तहत दर्ज किए गए बयानों का विकल्प नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं कहा जा सकता है। उक्त बयानों को पढ़ने के बाद, मुझे प्रत्यर्थी **के** सुस्पष्ट अभिवचन को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है कि यदि बच्चा याचिकाकर्ता के साथ अमेरिका में रहने लग जाता है, तो वह एक खुशहाल व्यक्ति के रूप में बड़ी नहीं हो सकती है।

50. मैंने ***ला मुस्गा (पूर्वोक्त), दघिर (पूर्वोक्त)*** और ***पोलक (पूर्वोक्त)*** के पुनर्विवाह के निर्णयों पर भी विचार किया है, जिस पर प्रत्यर्थी ने भरोसा किया है लेकिन पाया है कि वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं। इनमें से कोई भी निर्णय किसी भी व्यापक प्रतिपादना को निर्धारित नहीं करता है जैसा कि सुश्री लूथरा द्वारा तर्क दिया गया है कि एक बच्चे को कभी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां वह नियमित रूप से रह रहा था। मेरे विचार में, यह प्रश्न कि क्या संरक्षक माता-पिता को बच्चे के साथ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर रहने देने की अनुमति दी जानी चाहिए, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। संरक्षक माता-पिता के पुनर्वास के लिए ऐसे अनुरोधों पर निर्णय लेते समय कोई सीधा-सीधा सूत्र निर्धारित या पालन नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, मेरी सुविचारित राय है कि यह निश्चित रूप से बच्चे के हित में होगा कि वह अपनी माँ के साथ अमेरिका में बस जाए और प्रत्यर्थी को वीडियो कॉल द्वारा स्वतंत्र रूप से बातचीत करने की अनुमति देकर उसके अधिकारों की पर्याप्त रूप से रक्षा की जा सकती है और साथ ही उसे छुट्टियों के दौरान बच्चे की विशेष संरक्षण भी दी जा सकती है जब याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसे भारत लाया गया है।

51. इससे पहले कि मैं निष्कर्ष निकालूं, मैं यह भी ध्यान दे सकता हूँ कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के लापरवाह माँ होने के बारे में व्यापक प्रस्तुतियाँ दी हैं

क्योंकि बच्चे के कुछ टीकाकरण में कुछ महीनों की देरी हुई है। हालाँकि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये घटनाएं मई, 2019 से पहले की अवधि से संबंधित हैं, जब प्रत्यर्थी स्वेच्छा से सहमत हुआ कि बच्ची की संरक्षण याचिकाकर्ता के पास होनी चाहिए, मैं इन पहलुओं का निपटान करना आवश्यक नहीं समझता हूँ।

52. उपरोक्त के आलोक में, आक्षेपित आदेश, असंधार्य होने के कारण, तदनुसार अपास्त किया जाता जाता है। जबकि याचिकाकर्ता द्वारा रहने की माँग करने वाले दायर आवेदन को अनुमति दी जाती है, प्रत्यर्थी द्वारा दायर आवेदनों को खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता को नाबालिग बच्ची सुश्री अनीशा के साथ अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाती है। हालाँकि, यह निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(क) प्रत्यर्थी को हर शनिवार और रविवार को एक घंटे के लिए और अन्य दिनों में पांच से दस मिनट के लिए वीडियो कॉल द्वारा या किसी भी उपयुक्त वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर बच्चे के साथ बातचीत करने की स्वतंत्रता होगी।

(ख) याचिकाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली में बच्चे की उपस्थिति, साल में एक बार उसकी छुट्टियों के दौरान, कम से कम तीन सप्ताह की अवधि के लिए हो, जब तक कि किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रतिबंधों लगाने के कारण यात्रा रोकी न गयी हो। इस

अवधि के दौरान, प्रत्यर्थी को बच्चे की विशेष संरक्षण का अधिकार होगा।

(ग) यदि प्रत्यर्थी फीनिक्स, एरिजोना, अमेरिका की यात्रा करता है, तो वह सप्ताहांत में बच्चों से मिलने का हकदार होगा, बशर्ते कि पक्षकारों और बच्ची को आपस में सुविधा हो। हालाँकि, यदि उसकी यात्रा बच्चे की छुट्टियों के दौरान होती है, तो वह पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए जाने वाले दिनों की संख्या के लिए बच्चे की संरक्षण का हकदार होगा, वो दिन तब तीन सप्ताह की अवधि से बाहर रखा जाएगा जैसा कि यहाँ उपर खंड (ख) में निर्देशित किया गया है।

(घ) याचिकाकर्ता, एक सप्ताह के भीतर, इस आदेश द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक वचन पत्र दायर करेगा। याचिकाकर्ता अपने वचन पत्र में यह भी प्रावधान करेगी कि वह इस न्यायालय की अनुमति के बिना बच्चे के साथ किसी अन्य देश में नहीं रहेगी। हालाँकि, यह याचिकाकर्ता को छुट्टियों में नाबालिग बच्चे को फीनिक्स, एरिज़ोना, अमेरिका से बाहर ले जाने से नहीं रोकेगा।

(ङ) वचन पत्र की एक प्रति विद्वान कुटुम्ब न्यायालय के अभिलेख पर भी रखी जाएगी।

53. याचिका, सभी लंबित आवेदनों के साथ, उपरोक्त शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है।

(न्या. रेखा पल्ली)

फरवरी 03, 2023/ए.सी.एम.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*